अनुमान ९० लाख वार्षिक है। १९६०-६१ तक प्रत्येक की मांग बढ़ कर १.६० करोड़ तक हो जाने की आशा है।

साइकल के टायर और ट्यूब

१९७. {श्री म० ला० द्विवेदी : श्री दामानी :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५१ से १९५८ तक अब तक प्रतिवर्ष साइकल के टायर और ट्यूब का विक्रय मल्य क्या रहा है ;

(ख) ये चीजें बाजार में उपभोक्ताओं को किस भाव पर मिलती हैं ; और

(ग) सरकार द्वारा निश्चित दर पर उपभोक्ताओं को टायर और ट्यूब उपलब्ध कराने के लिये क्या कदम उठाने का विचार है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) मूल्यों का ब्यौरा इस प्रकार है :—

देश में बने टायरों (डनलप बेट्स और फायरस्टोन रोडमास्टर) तथा ट्यूबों के "सूची मूल्य" १९५१ से १९५७ तक निम्नानुसार थे :—

वर्ष	टायर	ट्यूब
१९५१	६ रु० ४ आ०	३ रु० ४ आ०
१९५२	५ रु० १२ आ०	२ रु० ८ आ०
१९५३	५ रु० ४ आ०	२ रु० ८ आ०
१९५४	५ रु० २ आ०	२ रु० ७ आ०
१९५५	४ रु० १० आ०	२ रु० ३ आ०
१९५६	५ रु० ७ आ०	२ रु० ३ आ०
१९५७	४ रु० ६२ न० पै०	२ रु० १९ न० पै०

चालू मूल्य वही है जो १९५७ में थे।

(ख) और (ग). निर्माता तो यही आशा करते हैं कि विक्रेता साइकल के टायर और ट्यूबों की सूची में दिये गये भावों पर बेचेंगे। लेकिन चूंकि माल काफी नहीं होता है, इसलिये सरकार साइकिल के टायरों और ट्यूबों (तथा रोजमर्रा के काम में आने वाली दूसरी महत्वपूर्ण चीजों) के भावों के रुख पर निगाह रखती आ रही है और स्थिति के अनुसार जो संभव होता है, रोकथाम करने के कदम उठाती है। चूंकि सूची में दिये गये भाव से अधिक दाम पर साइकिल के टायर बिकने के कुछ मामलों का पता सरकार को चला है, इसलिये उसने निर्माताओं को यह पक्का कर लेने की सलाह दी है कि विक्रेता सूची में दिये गये भावों से अधिक दाम न ले सकें। इसके साथ ही पुराने आयातकों का कोटा बढ़ा दिया गया है जिससे अधिक माल मिल सके। देश में उत्पादन बढ़ाने की दृष्टि से वर्तमान कारखानों को अतिरिक्त क्षमता स्थापित करने की मंजूरी दे दी गई है। इन योजनाओं को क्रियान्वित किया जा रहा है।

Agriculturist Displaced Persons in Rajasthan

1998. **Shri Shobha Ram:** Will the Minister of **Rehabilitation and Minority Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the amount which is charged in the shape of rent from the agriculturist displaced persons in Matsya Division in Rajasthan is more than the land revenue charged by the State Government from local agriculturists over the non-evacuee agricultural land; and

(b) whether Government is contemplating to charge the rent equivalent to land revenue?

The Deputy Minister of Rehabilitation (Shri P. S. Naskar): (a) and (b). Information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha in due course.